



INDIAN POLITY BY-SUJEET BAJPAI SIR





While Proclamation of Emergency is in operation, the term of the Lok Sabha can be extended for a period not exceeding?

जबिन आपातकाल की उद्घोषणा चल रही है, लोकसभा का कार्यकाल उससे अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है?

- (a) Six weeks
- (b) Three months
- (c) Six months
- (d) One year



Which one among the following has the power to regulate the right of citizenship in India?

निम्नलिखित में से किस एक के पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है?

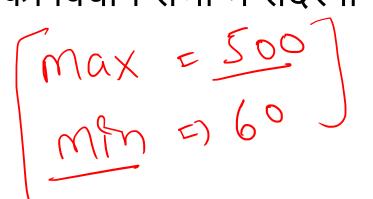
- (a) The Union Cabinet
- (b) The Parliament
- (c) The Supreme Court
- (d) The Law Commission



As per the Constitution of India, what is the limit prescribed for the number of members in the Legislative Assembly of a State?

भारत के संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधान सभा में सदस्यों की संख्या के लिए क्या सीमा निर्धारित है?

- (a) 350 members
- (b) 400 members
- (c) 450 members
- (d) 500 members





Which one of the following statements is/are correct with regard to the Vice-President of India?

- 1. He must be a member of Parliament.
- 2. He is elected by proportional representation.
- 3. He is Ex-officio Chairman of the Rajya Sabha.



भारत के उप-राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही है/क्या है? 1. वह संसद सदस्य होना चाहिए ।

- 2. वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुना जाता है।
- 3. वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं।



Select the correct answer unsig the code given below:

- (a) 1 only
- (b) 1 and 3
- (c) 2 and 3
 - (d) 1 and 2



Which of the following are the principles of the Panchsheel?

- 1. Peaceful co-existence
- 2. Mutual protection of the environment X
- 3. Mutual protection of indigenous population.
- 4. Mutual non-aggression



निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत पंचशील के हैं?

- 1. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व
- 2. पर्यावरण की पारस्परिक सुरक्षा
- 3. स्वदेशी आबादी का पारस्परिक संरक्षण।
- 4. आपसी गैर आक्रामकता



Select the correct answer using the code given below:

- (a) 2 and 3 only
- (b) 1 and 2 only
- (c) 1, 2 and 4
- (d) 1 and 4 only



Who among the following was the advisor of the Drafting Committee of the Constituent Assembly?

निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की मसौदा समिति का सलाहकार था?

- (a) B. Shiva Rao
- (b) Dr. B.R. Ambedkar
- (c) Sachidananda Sinha
- (c) B.N. Rao

Numbers	Subject Matter	Articles Covered
First Schedule	1. Names of the States and their territorial jurisdiction.	1 and 4
	2. Names of the Union Territories and their extent.	
Second Schedule	Provisions relating to the emoluments, allowances, privileges and so on of:	59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 & 221
	The President of India	
	2. The Governors of States	
	 The Speaker and the Deputy Speaker of the Lok Sabha 	
	4. The Chairman and the Deputy Chairman of the Rajya Sabha	
	The Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly in the states	
	6. The Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council in the states	
	7. The Judges of the Supreme Court	
	8. The Judges of the High Courts	



Sch.

Sch.

Lexbra Infor

related to

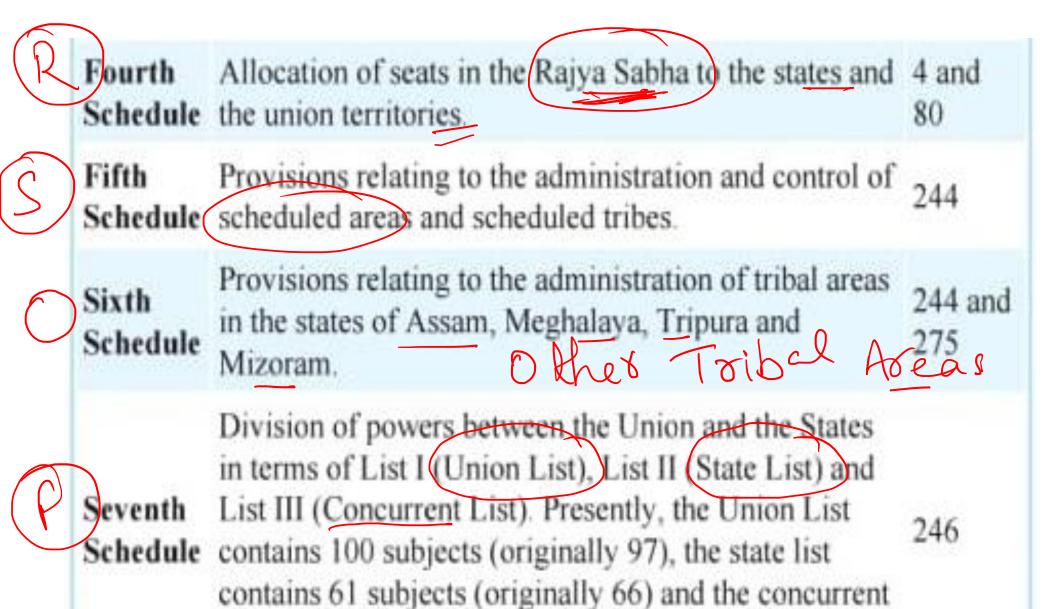
Art.



TEARS

Third Schedule	9. The Comptroller and Auditor-General of India 75, 84, 99, 124 146, 173, 188 an 219	
	1. The Union ministers	
	2. The candidates for election to the Parliament	
	3. The members of Parliament	
	4. The judges of the Supreme Court	
	5. The Comptroller and Auditor-General of India	
	6. The state ministers	
	7. The candidates for election to the state legislature	
	8. The members of the state legislature	

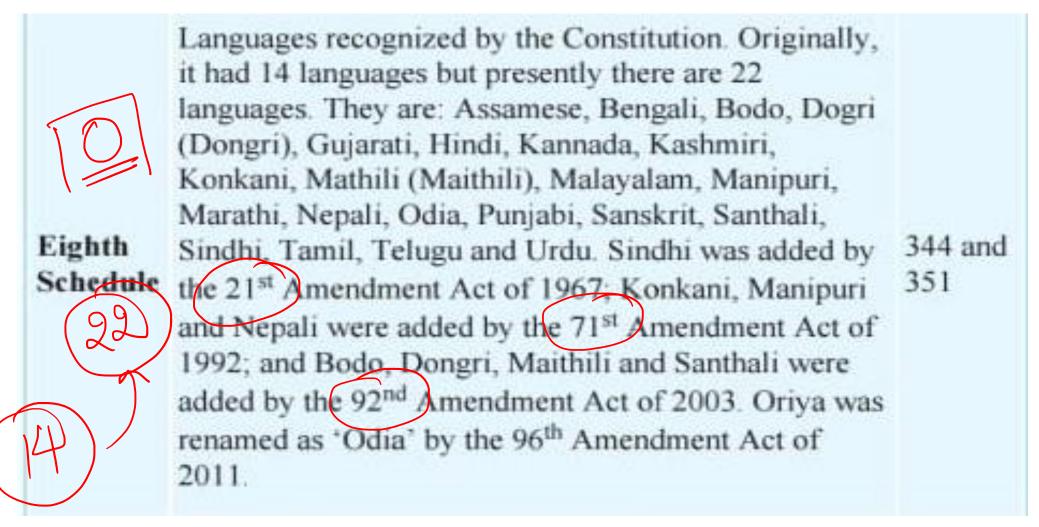
9. The judges of the High Courts



list contains 52 subjects (originally 47).







Land Deforms



31-B

Ninth Schedule

Acts and Regulations (originally 13 but presently 282)19 of the state legislatures dealing with land reforms and abolition of the zamindari system and of the Parliament dealing with other matters. This schedule was added by the 1st Amendment (1951) to protect the laws included in it from judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights. However, in 2007, the Supreme Court ruled that the laws included in this schedule after April 24, 1973, are now open to judicial review.





Tenth Schedule Provisions relating to disqualification of the members of Parliament and State Legislatures on the ground of defection. This schedule was added by the 52nd Amendment Act of 1985, also known as Anti-defection Law.

102 and 191



Eleventh Schedule Specifies the powers, authority and responsibilities of Panchayats. It has 29 matters. This schedule was added by the 73rd Amendment Act of 1992.

243-G



Specifies the powers, authority and responsibilities of

क्र. सं.	विषय	संबद्ध अनुच्छेद
प्रथम अनुसूची	 राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं 	1 एवं 4
दूसरी अनुसूची	परिलब्धियां पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान 1. भारत के राष्ट्रपति 2. राज्यों के राज्यपाल 3. लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 4. राज्यसभा के सभापति और उप-सभापति 5. राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 6. राज्य विधान परिषदों के सभापति और उप-सभापति 7. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश	59,65,75,97, 125,148,158,164, 186, एवं 221
	 राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्य विधान परिषदों के सभापित और उप-सभापित 	



तीसरी अनुसूची

इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं ये उम्मीदवार हैं:

75,84,99,124,146, 173,188 एवं 219

- 1. संघ के मंत्री
- 2. संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी
- 3. संसद के सदस्य
- 4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- 5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- 6. राज्य मंत्री
- 7. राज्य विधानमण्डल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी
- 8. राज्य विधानमण्डल के सदस्य
- 9. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश



चौथी अनुसूची	राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन।	4 एवं 80
पांचवीं अनुसूची	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध	244
छठी अनुसूची	असम, मेघालय , त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध	244 एवं 275
सातवीं अनुसूची	संघ सूची (मूल रूप से 97 मगर फिलहाल 100 विषय), राज्य सूची (मूल रूप से 66 मगर फिलहाल 61 विषय) तथा समवर्ती सूची (मूल रूप से 47, फिलहाल 52 विषय) के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन।	246
आठवीं अनुसूची	संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं (मूल रूप से 14 मगर फिलहाल 22)। ये भाषाएं हैं- असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तिमल, तेलुगू तथा उर्दू, सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली	344 एवं 351

E 100 TO 100 TO



को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा और बोड़ो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 'उड़िया' का नाम बदलकर 2011 में 'ओडिया' कर दिया।

नवीं अनुसूची

भू-सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमण्डलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम (मूलत: 13 परन्तु वर्तमान में 282)। ¹⁹ इस अनुसूची को पहले संशोधन (1951) द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंधन के आधार पर न्यायिक संवीक्षा से इसमें सिम्मिलत कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल, 1975 के बाद सिम्मिलत कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

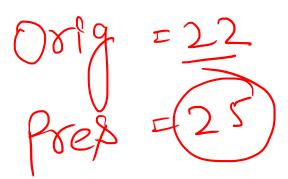
31-ख



दसवीं अनुसूची	दल-बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबंध, इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल-परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है।	102 एवं 191
ग्यारहवीं अनुसूची	पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।	243-ন্ত
बारहवीं अनुसूची	नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।	243-ब

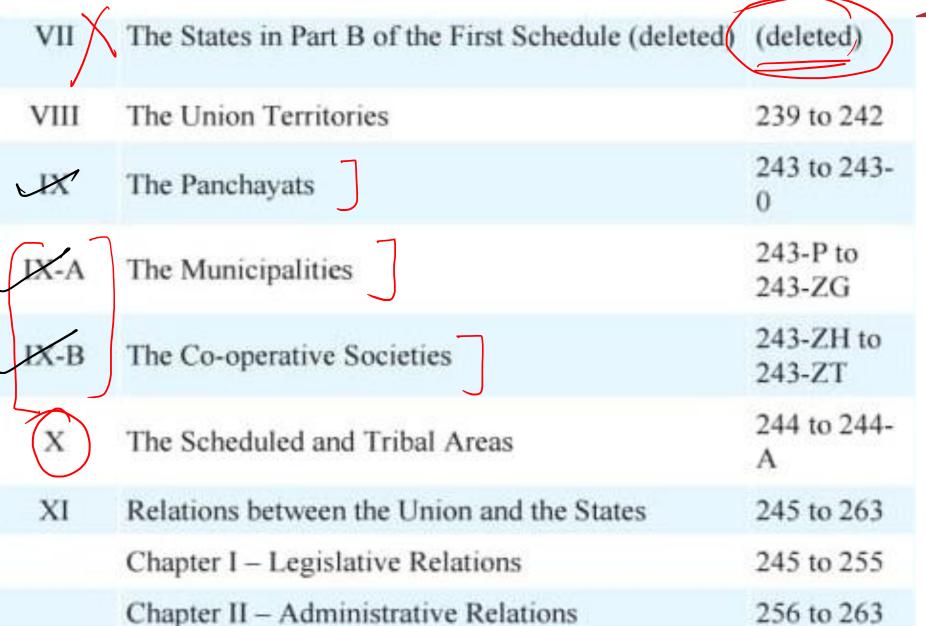
Parts	Subject Matter	Articles Covered
1	The Union and its territory	1 to 4
	Citizenship	5 to 11
M	Fundamental Rights	12 to 35
IV	Directive Principles of State Policy	36 to 51
W-A	Fundamental Duties	51-A
X	The Union Government	52 to 151
L	Chapter I – The Executive	52 to 78
	Chapter II – Parliament	79 to 122
	Chapter III - Legislative Powers of President	123
	Chapter IV - The Union Judiciary	124 to 147
	Chapter V – Comptroller and Auditor-General of India	148 to 151







V	The State Governments	152 to 237
	Chapter I – General	152
	Chapter II – The Executive	153 to 167
	Chapter III - The State Legislature	168 to 212
	Chapter IV - Legislative Powers of Governor	213
	Chapter V – The High Courts	214 to 232
	Chapter VI – Subordinate Courts	233 to 237
		238





		(3/5)	SAFALTA CLASS™
XI	Relations between the Union and the States	245 to 263	An Initiative by अमरउजाला
	Chapter I – Legislative Relations	245 to 255	
	Chapter II - Administrative Relations	256 to 263	
XII	Finance, Property, Contracts and Suits	264 to 300- A	
	Chapter I – Finance	264 to 291	
	Chapter II – Borrowing	292 to 293	
	Chapter III – Property, Contracts, Rights, Liabilities, Obligations and Suits	294 to 300	
	Chapter IV - Right to Property	300-A	
XIII	Trade, Commerce and Intercourse within the Territory of India	301 to 307	
XIV	Services under the Union and the States	308 to 323	
	Chapter I – Services	308 to 314	
	Chapter II - Public Service Commissions	315 to 323	
		323-A to	



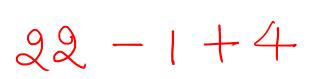
	(4A)	
XIV,A	Tribunals	323-B
XV	Elections	324 to 329- A
XVI	Special Provisions relating to Certain Classes	330 to 342
XVII	Official Language	343 to 351
	Chapter I - Language of the Union	343 to 344
	Chapter II - Regional Languages	345 to 347
	Chapter III—Language of the Supreme Court, High Courts, and so on	348 to 349
	Chapter IV—Special Directives	350 to 351



		~
XVIII	Emergency Provisions	352 to 360
XIX	Miscellaneous	361 to 367
XX	Amendment of the Constitution	368
XXI	Temporary, Transitional and Special Provisions	369 to 392
XXII	Short title, Commencement, Authoritative Text in Hindi and Repeals	393 to 395









भाग	विषय	संबद्ध अनुच्छेद
I	संघ और उसका राज्य क्षेत्र	1 से 4
II	नागरिकता	5 से 11
III	मौलिक अधिकार	12 से 35
ĮV.	राज्य की नीति के निदेशक तत्व	36 से 51
IVΨ	मौलिक कर्तव्य	51-क



V	संघ सरकार	52 से 151
	अध्याय-I-कार्यपालिका	52 से 78
	अध्याय-II-संसद	79 से 122
	अध्याय-III-राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां	123
	अध्याय-IV-संघ की न्यायपालिका	124 से 147
	अध्याय-V-भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	148 से 151
VI	राज्य सरकारें	152
	अध्याय-I-साधारण	152 से 237
	अध्याय-॥-कार्यपालिका	153 से 167
	अध्याय-III-राज्य का विधानमंडल	168 से 212
	अध्याय-IV-राज्यपाल की विधायी शक्तियां	213



	अध्याय-V-राज्यों के उच्च न्यायालय	214 से 232
	अध्याय-VI-अधीनस्थ न्यायालय	233 से 237
VII	राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड-ख (निरस्त))	238 निरस्त
VIII	संघ राज्य क्षेत्र	239 से 242
IX	पंचायतें	243 से 243-ण
IXक	नगरपालिकाएं	243-त से 243-छ
IX ख	सहकारी समितियां	243-ZH से 243-ZT
X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244 से 244-क
XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध	245 से 263
	अध्याय-I-विधायी संबंध	245 से 255
	अध्याय-11-प्रशासनिक संबंध	256 से 263



XII	वित्त, संपत्ति, संविदायें और वाद	264 से 300-1
	अध्याय-I-वित्त	264 से 291
	अध्याय-II-ऋण लेना	292 से 293
	अध्याय-III-संपत्ति, संविदायें, अधिकार, बाध्य ताएं और वाद	294 से 300
	अध्याय-IV-संपत्ति का अधिकार	300-क
XIII	भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम	301 से 307
XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं	308 से 323
	अध्याय-I-सेवायें	308 से 314
	अध्याय-II-लोक सेवा आयोग	315 से 323
XIV _क	अधिकरण	323-क से 323- ख
xv	निर्वाचन	324 से 329-क
XVI	कुछ वर्गों से सम्बन्धित विशेष प्रावधान	330 से 342
XVII	राजभाषा	343 से 351
	अध्याय-I-संघ की भाषा	343 से 344
	अध्याय-II-प्रादेशिक भाषाएं	345 से 347
	अध्याय- -सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा	348 से 349
	अध्याय-IV-विशेष निदेश	348 से 349



XVIII	आपात उपबंध	352 से 360
XIX	प्रकीर्ण	361 से 367
XX	संविधान का संशोधन	368
XXI	अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध	369 से 392
XXII	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	393 से 395



Preamble of the Constitution

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a '[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC] and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the ²[unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.







Ingredients of the Preamble The Preamble reveals four ingredients or components:

1.

Source of authority of the Constitution: The Preamble states that the Constitution derives its authority from the people of India.



प्रस्तावना प्रस्तावना से चार अवयवों या घटकों का पता चलता है:

1. संविधान के अधिकार का स्रोत: प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है ।



2.

Nature of Indian State: It declares India to be of a sovereign, socialist, secular democratic and republican polity.

3.

Objectives of the Constitution: It specifies justice, liberty, equality and fraternity as the objectives.



2.

भारतीय राज्य की प्रकृति:

यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और रिपब्लिकन राजनीति का घोषित करता है।

3.

संविधान के उद्देश्य:

यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट करता है ।



4.

Date of adoption of the Constitution: It stipulates November 26, 1949 as the date.

संविधान को अपनाने की तिथि: इसमें 26 नवंबर, 1949 को तारीख निर्धारित की गई है।



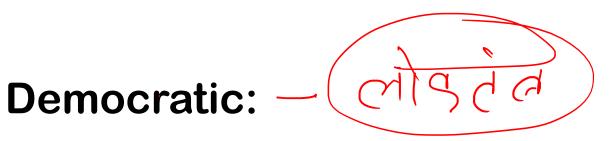
Key Words in the Preamble Certain key words—

Sovereign: - Lygg interfer X
externd interfer



Socialist:

Secular: _ State has no religion





Republic:

(1101(Ja)

tead of state releated by people. (Dire OR) Indir.)



Justice:

Liberty:

Equality:

Fraternity:



Popular Statements About Preamble:

Sir Alladi Krishnaswami Iyer, a member of the Constituent Assembly who played a significant role in making the Constitution, 'The Preamble to our Constitution expresses what we had thought or dreamt so long'.



प्रस्तावना के बारे में लोकप्रिय बयान:

संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, जिन्होंने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, हमारे संविधान की प्रस्तावना व्यक्त करती है कि हमने जो सोचा था या इतना लंबा सपना देखा था।





According to K M Munshi, a member of the Drafting Committee of the Constituent Assembly, the Preamble is the 'horoscope of our sovereign democratic republic'.

संविधान सभा की मसौदा समिति के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है ।



M Hidayatullah, a former Chief Justice of India, observed, "It is the heart & soul of our Constitution".

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह संविधान का हृदय और आत्मा है



Preamble as Part of the Constitution

1. Berubari Union case (1960):

Preamble is not a part of the Constitution.

2. Kesavananda Bharati case(1973):

Preamble is a part of the Constitution.



NOTE:

- 1. The Preamble is neither a source of power to legislature nor a prohibition upon the powers of legislature.
- 2. It is non-justiciable, that is, its provisions are not enforceable in courts of law.



नोट:

1. प्रस्तावना न तो विधायिका को शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध है ।

2. यह गैर-बदनाम है, अर्थात न्यायालयों में इसके प्रावधान लागू नहीं है।



Amendability of the Preamble:





The Preamble has been amended only once so far, in 1976, by the 42nd Constitutional Amendment Act, which has added three new words—Socialist, Secular and Integrity—to the Preamble.



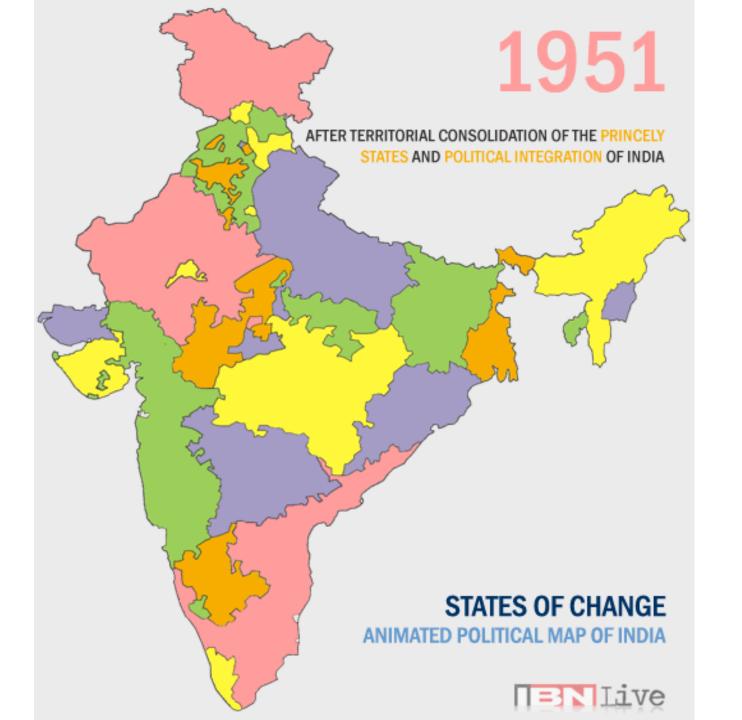
प्रस्तावना की संशोधन:

हाँ

प्रस्तावना में 1976 में 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केवल एक बार संशोधन किया गया है, जिसमें तीन नए शब्दों-समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया है।



Union and its Territory



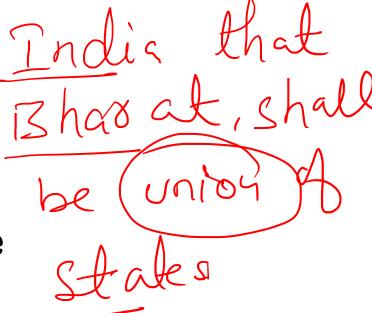


1947 =>



According to Article 1, the territory of India can be classified into three categories:

- 1. Territories of the states
- 2. Union territories
- 3. Territories that may be acquired by the Government of India at any time.





अनुच्छेद् 1 के अनुसार, भारत के क्षेत्र को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- 1. राज्यों के प्रदेशों
- 2. केंद्र शासित प्रदेश
- 3. ऐसे क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत किए जा सकते हैं।



Article 2 grants two powers to the Parliament:

- (a) the power to admit into the Union of India new states; and
- (b) the power to establish new states.
- अनुच्छेद 2 संसद को दो शक्तियां प्रदान करता है:
- (क) भारत के नए राज्यों के संघ में प्रवेश करने की शक्ति;
- और
- (ख) नए राज्यों की स्थापना की शक्ति ।



The first refers to the admission of states which are already in existence while the second refers to the establishment of states which were not in existence before.

पहला उन राज्यों के प्रवेश को संदर्भित करता है जो पहले से अस्तित्व में हैं जबकि दूसरा उन राज्यों की स्थापना को संदर्भित करता है जो पहले अस्तित्व में नहीं थे।





Article 3, on the other hand, relates to the formation of or changes in the existing states of the Union of India.

In other words, Article 3 deals with the internal re-adjustment of the territories of the constituent states of the Union of India.



दूसरी ओर अनुच्छेद 3 भारत संघ के मौजूदा राज्यों के गठन या बदलाव से संबंधित है।

दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 3 भारत संघ के घटक राज्यों के क्षेत्रों के आंतरिक पुन समायोजन से संबंधित है।

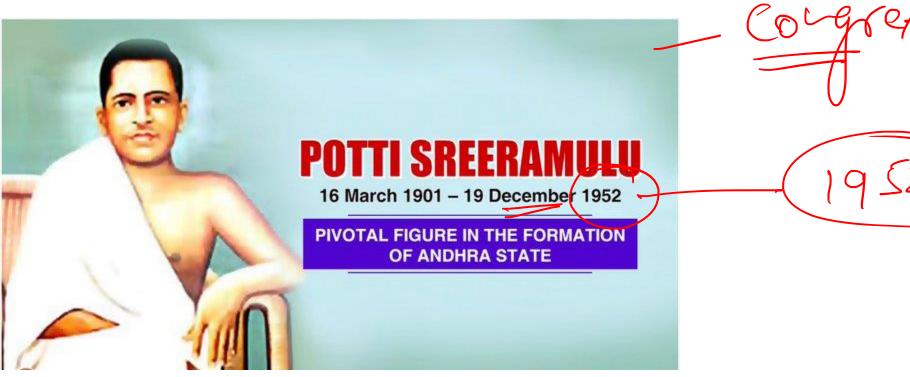


An Initiative by अमर उजाला



LJVC - MUX





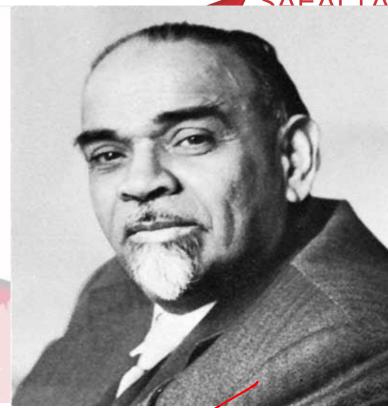






Pandit Hriday Nath Kunzru







Dhar Commission and JVP Committee:

The integration of princely states with the rest of India has purely an ad hoc arrangement. There has been a demand from different regions, particularly South India, for reorganisation of states on linguistic basis.



धर आयोग और जेवीपी समिति:

शेष भारत के साथ रियासतों के एकीकरण में विशुद्ध रूप से तदर्थ व्यवस्था है।

भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर दक्षिण भारत से मांग की गई है।



Accordingly, in June 1948, the Government of India appointed the Linguistic Provinces Commission under the chairmanship of S K Dhar to examine the feasibility of this.

The commission submitted its report in December 1948 and recommended the reorganisation of states on the basis of administrative convenience rather than linguistic factor.



तदनुसार, जून 1948 में भारत सरकार ने इसकी व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की।

आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और भाषाई फैक्टर के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के प्नर्गठन की सिफारिश की।



This created much resentment and led to the appointment of another Linguistic Provinces Committee by the Congress in December 1948 itself to examine the whole question afresh.

इससे काफी नाराजगी पैदा हुई और दिसंबर 1948 में ही कांग्रेस द्वारा एक और भाषाई प्रांत समिति की नियुक्ति कर इस पूरे सवाल की नए सिरे से जांच की गई।



It consisted of Jawaharlal Nehru, Vallahbhai Patel and Pattabhi Sitaramayya and hence, was popularly known as JVP Committee.

It submitted its report in April 1949 and formally rejected language as the basis for reorganisation of states.



इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लाहभाई पटेल और पट्टाभि सीतारामैया शामिल थे और इसलिए उन्हें जेवीपी कमेटी के नाम से जाना जाता था।

इसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और औपचारिक रूप से भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में अस्वीकार कर दिया ।



However, in October 1953, the Government of India was forced to create the first linguistic state, known as Andhra state, by separating the Telugu speaking areas from the Madras state.

This followed a prolonged popular agitation and the death of Potti Sriramulu, a Congress person of standing, after a 56-day hunger strike for the cause.



हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र राज्य के नाम से जाना जाने वाला पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

इसके बाद लंबे समय तक लोकप्रिय आंदोलन चला और कांग्रेस के खड़े व्यक्ति पोट्टी श्रीरामुलु की मौत के बाद 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इस कारण से मौत हो गई।



Fazl Ali Commission

The creation of Andhra state intensified the demand from other regions for creation of states on linguistic basis.

This forced the Government of India to appoint (in December 1953) a three-member States Reorganisation Commission under the chairmanship of Fazl Ali to re-examine the whole question.



फजल अली आयोग

आंध्र राज्य के निर्माण से भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए अन्य क्षेत्रों से मांग तेज हो गई।

इससे भारत सरकार को (दिसंबर 1953 में) फजल अली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने को मजबूर होना पड़ा और पूरे सवाल की फिर से जांच की गई।



Its other two members were K M Panikkar and H N Kunzru.

It submitted its report in September 1955 and broadly accepted language as the basis of reorganisation of states. But, it rejected the theory of 'one language-one state'.

Its view was that the unity of India should be regarded as the primary consideration in any redrawing of the country's political units.



इसके अन्य दो सदस्य केएम पाणिकर और एच एन कुंजरू थे।

इसने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में मोटे तौर पर भाषा को स्वीकार किया।

लेकिन, इसने 'एक भाषा-एक राज्य' के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसका विचार यह था कि देश की राजनीतिक इकाइयों को फिर से तैयार करने में भारत की एकता को प्राथमिक विचार माना जाना चाहिए।